

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 80 / 2023 अपील (GCMS 2023/84)

पंजीयन दिनांक– 11 / 09 / 2023

निर्णय दिनांक– 25 / 08 / 2025

1. श्री डालचंद पिता हेमा उर्फ हेमराज अहीर, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
2. श्रीमती गंगाबाई पत्नि हेमा उर्फ हेमराज अहीर, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
3. श्री माधवलाल पिता हेमा उर्फ हेमराज अहीर, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
4. श्री कैलाशचन्द्र पिता डालचंद अहीर, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।

—अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई पिता चतरभुज जाट पत्नि रतनलाल जाट, निवासी वगतपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद ।
2. श्री नारू पिता चतरभुज जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
3. श्री माधुलाल पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
4. श्री कालुराम पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
5. कमलाबाई पुत्री प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
6. श्री मुकेश पिता चुना जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।

—रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता अपीलांट्स

प्रकरण संख्या – 127 / 2023 अपील (GCMS 2023/130)

पंजीयन दिनांक– 11 / 09 / 2023

निर्णय दिनांक– 25 / 08 / 2025

1. श्री नारू पिता चतरभुज जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
2. श्री माधुलाल पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
3. कमलाबाई पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
4. श्री मुकेश पिता चुना जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।

—अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई पिता चतरभुज जाट पत्नि रतनलाल जाट, निवासी वगतपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद ।
2. श्री कालुराम पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत अधिवक्ता अपीलांट्स

प्रकरण संख्या – 232 / 2023 अपील (GCMS 2023/239)

पंजीयन दिनांक– 11 / 10 / 2023

निर्णय दिनांक– 25 / 08 / 2025

1. श्री सुरेशचन्द्र पिता लेहरूलाल जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
2. श्री जगदीश पुत्र सोहनीदेवी, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
3. श्री लक्ष्मीलाल सोहनीदेवी, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।

4. श्री मुकेश पुत्र सोहनीदेवी, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।

—अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई पिता चतरभुज जाट पत्नि रतनलाल जाट, निवासी वगतपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद ।
2. श्री नारू पिता चतरभुज जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
3. श्री माधुलाल पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
4. श्री कालुराम पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
5. कमलाबाई पुत्री प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
6. श्री मुकेश पिता चुना जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद ।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दुगासिंह शक्तावत अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2,3,5,6

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध, उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 01/2020 (ना. क. अपील) निर्णय दिनांक 18.01.2023

निर्णय

दिनांक 25/08/2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 01/2020 (ना. क. अपील) निर्णय दिनांक 18.01.2023 के विरुद्ध अपील संख्या 80/2023 दिनांक 14.07.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 96, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5

मयाद अधिनियम मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ तथा अपील संख्या 127/2023 दिनांक 21.02.2023 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के न्यायालय में पेश की गई। राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 एवं कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं सलूम्वर के राजस्व प्रकरणों के सूनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर को प्रदान किये जाने से उक्त हस्तगत अपीलें न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होने से इस न्यायालय में दिनांक 11.09.2023 को दर्ज की गई तथा अपील संख्या 232/2023 दिनांक 06.10.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 96, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 01/2020 निर्णय दिनांक 18.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त तीनों अपीलों का निस्तारण इस निर्णय से किया जा रहा है।

इन तीनों प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के न्यायालय में एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 13.11.1989 ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट के पिता चतरभुज के चार लडके प्यारचंद, नारू, मदनलाल, चुन्नीलाल व एक लडकी वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 उत्पन्न हुई थी। वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती

मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 चतरभुज की जाईन्दा संतान होकर नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 13.11.1989 ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में वर्णित कुल किता 29 आराजीयात कुल रकबा 263-02 बीघा में अपने हस्से से वंचित कर दिया गया था। अतः नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 13.11.1989 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामांतरकरण में वर्णित आराजीयात में वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 का नाम उसके हिस्से अनुसार अंकित फरमाया जावें। उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2020 निर्णय दिनांक 18.01.2023 से वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1/अपीलांट्स 2 की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपीलें पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.01.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:-**“अतः अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम जूणदा के ना. क. स. 702 निर्णय दिनांक 13.11.1989 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमियों के पूर्व खातेदार चतरभुज पिता रामलाल जाट के विधिक वारिसान की जांच कर व पक्षकारान् को सुनकर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।”**

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपील संख्या 80/2023 में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अपील संख्या 128/2023 में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना

के अनुपस्थित, अपील संख्या 232/2023 में अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित, रेस्पोंडेंट संख्या 2, 3, 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित शेष रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.08.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स अपील संख्या 80/2023 एवं 232/2023 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम जूणदा के खाता संख्या 531 में आराजी संख्या 757 रकबा 1.5297 हैक्टेयर, आराजी संख्या 750 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, आराजी संख्या 755 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, आराजी संख्या 756 रकबा 0.9712 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 3.9577 हैक्टेयर में अपीलांत संख्या 3 माधवलाल का 1/6 हिस्सा, अपीलांत संख्या 1 डालचंद का 1/6 हिस्सा, अपीलांत संख्या 4 कैलाशचन्द्र का 1/6 हिस्सा जमाबंदी संवत् 2074-2077 में राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 105 के आराजी संख्या 758 रकबा 11.5500 हैक्टेयर भूमि में अपीलांत संख्या 2 गंगाबाई का 29/102 हिस्सा, अपीलांत संख्या 1 डालचंद का 1/12 हिस्सा, अपीलांत संख्या 3 माधवलाल का 1/12 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार इसी अपीलाधीन आदेश की अन्य अपील में अपीलांत संख्या सुरेशचन्द्र के खाते में ग्राम जूणदा के खाता संख्या नया 883 में आराजी संख्या 2531 रकबा 8.7400 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा, अपीलांत संख्या 2, 3 व 4 की माता सोहनीदेवी के खाते में ग्राम जूणदा की आराजी संख्या 1324 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1645 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1649 रकबा 0.3885 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.1817 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था, जिसके अपीलांट्स खातेदार काश्तकार होकर अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरकरण की अपील में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा पक्षकार नहीं बनाया, जबकि खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाया जाना विधि अनुसार आवश्यक है। चतरभुज जाट का

निधन होने से सन् 1989 में उनके वारिसान के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 702 खुला एवं उनके वारिसान खातेदार काश्तकार के रूप में रेकर्ड में अंकित हुए। तत्पश्चात् रेस्पोंडेंट्स ने उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट्स को विक्रय की। इस प्रकार ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत क्रेतागण अर्थात् अपीलान्ट्स उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये। नामांतरकरण संख्या 702 दिनांक 13.11.1989 को पारित किया गया था, जिसकी अपील 31 वर्ष बाद सन् 2020 में पेश की गई, जो बैरून मयाद है एवं धारा 5 के प्रार्थना-पत्र में जो आधार लिये गये हैं, वह भी झुठे हैं। मयाद के बिन्दु पर प्रतिदिन की देरी का कारण बताना पडता है, लेकिन ऐसा कोई उचित कारण रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में नहीं बताया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम पर कोई आदेश ही पारित किया गया है। विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार नामांतरकरण की कार्यवाही के जरिये निरस्त नहीं किये जा सकते हैं, खातेदारी अधिकार सिर्फ घोषणा की डिक्री की पालना में ही निरस्त किये जा सकते हैं। अपीलान्ट्स सद्भावी क्रेता है एवं जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज जो अपीलान्ट्स के पक्ष में है, उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा दिया जाता तब तक नामांतरकरण के जरिये राजस्व रेकार्ड से नाम नहीं हटाया जा सकता है। अपीलान्ट्स सद्भावी क्रेता है एवं सद्भावी क्रेता को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरकरण बाबत जो कार्यवाही हुई है वह विधिनुसार नहीं हुई है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2023 को पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2006 (HC) Page 1085, RRT 2006 (SC) Page 350, RRT 2013 (SC) Page 887, DNJ 2007 (Raj) Page 1657, RRT 2010 (RB) Page 625, RRT 2010 (RB) Page 310, RRT 2010 (RB) Page 124, RRT 2010 (RB) Page

1222, का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधीवक्ता अपीलांट्स अपील संख्या 127/2023 तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2, 3, 5 व 6 अपील संख्या 232/2023 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांत मगनलाल की ओर से अपील विद्रो कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पीकिंग आदेश दिया जाना चाहिए था कि अपीलांत संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं रहेगा, यह आदेश न देकर अस्पष्ट आदेश दिया गया कि तहसीलदार, रेलमगरा चतरभुज पिता रामलाल जाट के वारिसान की जांच कर नामांतरकरण की कार्यवाही करे, जबकि मगनलाल को एक्सक्लूड करना चाहिए था, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने आप में विरोधाभाषी है। अपील के दौरान अपीलांट्स के द्वारा आदेश 41 नियम 3क के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवधि के बिन्दु पर पृथक से पहले सुनवाई कर प्रार्थना पत्र निर्णित करने की प्रार्थना की गई व उस प्रार्थना पत्र के जवाब में पत्रावली नियत थी। तब अपीलांत की ओर से अवधि एवं अपील दोनो को मेरिट पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर रेस्पोंडेंट ने जवाब बंद कराया। मेरिट का अर्थ अवधि के बिन्दु को पृथक से तय न कर अपील मेरिट पर निर्धारित की जाने पर सहमति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय में अपील अंदर अवधि में नहीं थी अथवा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया गया अथवा नहीं पर कोई आदेश न देकर सीधा ही अपील स्वीकार करने का आदेश प्रदान कर दिया गया। ऐसा आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.1989 के बाद की हुई देरी के बारे में एक शब्द भी अवधि कण्डोन करने हेतु अभिकथन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपने आप में देरी कण्डोन नहीं हो सकती है, अवधि कण्डोन किये जाने में अपीलांत की ओर से सहमति नहीं दी गई, बल्कि अपील को गुणावगुण पर निर्धारित करने पर सहमति दी गई। जिसका अर्थ

अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निकाला गया। अवधि के कण्डोन करने के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया 31 वर्ष की देरी से अपील प्रस्तुत करना, कोई कारण दर्शित नहीं करना, अवधि के बिन्दुओं को अंदर अवधि मान लिये जाने में सहमति नहीं दी गई। अवधि कण्डोन करने के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मौन है, जिससे उक्त आदेश/निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीवक्ता अपीलांट्स अपील संख्या 127/2023 तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2, 3, 5 व 6 अपील संख्या 232/2023 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2010 (1) Page 310, RRT 2010 (2) Page 1223, RRT 2010 (1) Page 125, DNJ 2007 (3) Page 1657, RRT 2010 (1) Page 625, RRT 2006 (2) Page 1085 का हवाला प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2023 में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था अतएवं उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं अपीलांट की अपील को न्यायहित में कण्डोन किया जाता है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के न्यायालय में एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 13.11.1989 ग्राम पंचायत

जूनदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट के पिता चतरभुज के चार लडके प्यारचंद, नारु, मदनलाल, चुन्नीलाल व एक लडकी वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 उत्पन्न हुई थी। वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 चतरभुज की जाईन्दा संतान होकर नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 13.11.1989 ग्राम पंचायत जूनदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में वर्णित कुल किता 29 आराजीयात कुल रकबा 263-02 बीघा में अपने हस्से से वंचित कर दिया गया है। अतः नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 13.11.1989 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामांतरकरण में वर्णित आराजीयात में वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 का नाम उसके हिस्से अनुसार अंकित फरमाया जावे। उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2020 निर्णय दिनांक 18.01.2023 से वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1/अपीलांट्स 2 की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपीलें पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मूल पुरुष श्री चरतभुज पिता रामलाल जाट, निवासी जूनदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद की मृत्यु के उपरांत उनके वारीसानों में चार पुत्र मगनलाल, प्यारचंद, नारु तथा चुन्नीलाल एवं एक पुत्री मांगीबाई है। चुन्नीलाल फौत होकर चुन्नीलाल के वारिस भैरूलाल व मुकेश है तथा भैरूलाल भी लाओलाद फौत हुआ एवं प्यारचंद का भी देहांत होने से उनके वारिस श्री माधुलाल, कालुलाल व कमलाबाई होना प्रकट होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि श्रीमती मांगीबाई की मौरुसी (पैतृक) संपत्ति है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रत्येक विधिक वारिसान को समान हक व अधिकार निहित कर रखा है।

हिन्दु उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 08 के अनुसार हिन्दु पुरुष की निर्वसियती मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति में उसके पुत्र एवं पुत्रियों को विरासतीय अधिकार रेस्पोंडेंट संख्या 1 मांगीबाई के होना प्रमाणित पाया जाता है।

इस प्रकरण में हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के धारा-8 व 10 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार:-

Section 8 provides for the general rules of succession applicable to the devolution of the property of a male Hindu dying intestate.⁴⁴ The property devolves firstly, on the heirs specified in Class I of the Schedule; if there is no heir of Class I, then, on the heirs specified in Class II; if there is no heir in any of the two classes, on agnates and if there are no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 9 provides for the order of succession among the heirs in the Schedule. Section 10 provides for the distribution of property among heirs in Class I of the Schedule in the following terms:

“10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.—

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—

Rule 1.— The intestate’s widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.— The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.— The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.— The distribution of the share referred to in Rule 3—

(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters gets equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.”

In terms of Section 10, the division of property of an intestate among the heirs in Class - I is governed by the four Rules extracted above. They stipulate that

(i) the widow or if there is more than one all of them together shall take one share;

(ii) the surviving sons and daughters and mother shall each take one share; and

(iii) heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter take between them one share.

Class-I of the Schedule is in the following terms:

“Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a predeceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a predeceased son of a pre-deceased son; [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a predeceased son].”

उपयुक्त क्रम में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नांकित दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना उचित समझते हैं जो हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष को साबित करते हैं:

**SUPREME COURT OF INDIA- Arunachala Gounder (Dead)
By Lrs. – Appellant Versus Ponnusamy And Ors. – Respondent,
Civil Appeal No. 6659 of 2011, Decided on : 20-01-2022**

(A) Hindu Succession Act, 1956 – Sections 14 and 15 – Female Hindu succession – Right of a widow or daughter to inherit self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements – If a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or a family property, same would devolve by inheritance and not by survivorship and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals. (Para 66)

इस आदेश में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 14 व 15 – महिला हिन्दु उत्तराधिकार – एक विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति या बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरुष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में पाने का अधिकारी न केवल पुराने प्रथागत हिन्दु कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है:– यदि बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरुष की संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति है या सहदायिक या पारिवारिक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई है, तो यह उत्तराधिकार के तहत प्राप्त होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा और ऐसे हिन्दु पुरुष की बेटी अन्य संपार्श्विक के मुकाबले ऐसी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामन्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में श्री चतरभुज पिता रामलाल जाट के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलाट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद का निर्णय दिनांक 18.01.2023 यथावत रखा जाता है तथा अपीलाट्स अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2023 में अंकित ऑब्जरवेशन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा के न्यायालय में चाराचोही करें।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर